विचार बिन्दु

अज्ञानी होना मनुष्य का असाधारण अधिकार नहीं है बल्कि स्वयं को अज्ञानी जानना ही उसका विशेषाधिकार है। –राधाकृष्णन

आज़ादी का अमृतकाल आ गया मगर असमानता नहीं मिटी

संविधान में समानता और न्याय को स्वतंत्र भारत का आदर्श बना देने के बाद भी समता वाले राज्य और समाज की रचना अब भी दिवास्वप्न ही बनी हुई है। सबको बराबरी का हक़ और संपन्नता में सबकी बराबर भागीदारी की पोल तो सरकारी आंकड़े ही खोलते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि जहां गरीबी और असमानता व्यापक रूप से मौजूद है वहीं एक छोटा सा तबका धन–धान्य में खेल रहा है। भारत में सिर्फ दस प्रतिशत लोगों के पास देश की आधे से भी ज्यादा 57 प्रतिशत संपत्ति है जबकि देश की आधी आबादी सिर्फ 13 प्रतिशत संपत्ति पर गुजारा करने को मजबूर है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राजनैतिक दलों की प्राथमिकता केवल सत्ता पाना रह गया है। सदियों से चले आ रहे सामंती व्यवहार वाले समाज को बदल कर उसे लोकतान्त्रिक मूल्यों से पोषित करने का काम राजनेताओं और राजनीति ने बहुत पहले ही छोड़ दिया। दुनिया में पहली बार राजनीति को पवित्र बनाने का प्रयत्न करने वाले महात्मा गांधी ने इसीलिए यह तज़बीज दी थी कि कांग्रेस को अपने को बदल कर ज़मीनी स्तर पर समाज को बदलने के काम करने में लग जाना चाहिये। वे जानते थे कि एक बराबरी वाला समाज बनाने के लिए समाज सेवा करने वालों को धरती पर जड़ों में काम करके लोगों के दिलों को बदलना होगा। बदलना भी जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्रेम से। लेकिन ब्रितानवी शासन की रुखसत के बाद जब गणतांत्रिक भारत बना तब संविधान की किताब तो हम भारत के लोगों के हाथ में आ गई मगर आगे की राह दिखाने के लिए गांधी न रहे और राजनीति भटकती ही चली गई। यह विडंबना ही है कि संवैधानिक की बेहतरीन व्यवस्थाओं के बावजूद सामाजिक और आर्थिक समानता वाला समाज देश के अमृतकाल के बाद भी नहीं बन सका है। अवसरों तथा आर्थिक असमानता तो सर्वत्र नज़र आती है। राजनीति से सेवा का भाव तिरोहित हो गया है। आज राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं का जैसा स्वरूप बन गया है वह राजनीतिक अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया का ही परिणाम हैं। जब यह कहा जाता है कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है तब उसका आशय संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षरण से होता है जिनमें संसद तथा विधानसभाएं भी शामिल है। लोकसभा तथा राजस्थान विधान सभा का पिछला पूरा कार्यकाल सदनों के उपाध्यक्ष का चुनाव किये बिना बीत गया, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने को तो लोकतंत्र संविधान की किताब से चलता है मगर असल में वह उसके नियंताओं की नीयत से चलता है। लोकतंत्र को तानाशाही हथकंडों से नहीं चलाया जा सकता। वह अत्यंत मुलायम सहमति से चलता है। लोकतंत्र से हमने सत्तावादी राजतंत्र जैसी पुरानी सामंती व्यवस्थाओं से आजादी पाने का हक़ पाया है। संविधान ने अपने अनुच्छेद 15 के जरिए भारत के लोगों को बुनियादी अधिकार दिए हैं जिसमें सब नागरिकों के बीच समानता की उद्घोषणा है। लेकिन समस्या आती है प्रतिस्पर्धी राजनीति में वर्ग, जाति और सामाजिक–धार्मिक समुदायों से जो राजनीति में घुन की तरह लग गए हैं। इन सारे वर्गों में उनके आंतरिक स्वरूप में भी भेदभाव वाले कड़े पदानुक्रम मौजूद हैं। न केवल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूहों के बीच, बल्कि कमजोर समुदाय के भीतर भी पदानुक्रम असमानता है जो संवैधानिक प्रावधानों से नहीं सामाजिक अभियानों से ही हटाई जा सकती है, मगर राजनेताओं ने अपने हित साधने के लिए चुनावों में इस सामाजिक भेद का उपयोग करते हुए उसे अनौपचारिक रूप से संस्थागत बना रखा हैं। समतावादी समाज की रचना में राजनेताओं की कोई रुचि नहीं नहीं नज़र आती। इससे समस्त वैधानिक व्यवस्थाओं के बावजूद अंत्योदय की बात किताबों में पढ़ने तक सीमित रह जाती है और व्यवहार में नहीं आती।

संविधान राज्य से अपेक्षा करता है कि वह सबके साथ समता से व्यवहार करेगा। किन्तु विडंबना यह है कि राज्य ने खुद वर्गों के पैमाने बना दिए हैं। जैसे वह एक वर्ग सरकारी कर्मियों के जीवन यापन के लिए अलग पैमाना तथा दूसरे वर्गों के लिए अलग पैमाना रखता है। देश की 70 प्रतिशत जनता गरीब है, यह प्रधानमंत्री भी मानते हैं। कोई पूछे कि ऐसे में सरकारी कर्मचारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा कॉर्पोरेट जगत के लोगों की प्रतिव्यक्ति आय गरीबों की प्रतिव्यक्ति आय से कितनी गुना अधिक है और क्यों है? मानव विकास के संकेतक लगातार इस आर्थिक असमानता की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं लेकिन दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने तथा उच्च आर्थिक विकास दर के बावजूद असमानता की यह खाई बनी हुई है। नई बाज़ारोन्मुख अर्थव्यवस्था में देश के विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूह अपने–अपने लिए कुछ लाभ प्राप्त करने और उन्हें सुरक्षित रखने के प्रयत्न में ही लगे नज़र आते हैं। यह भी सामने दिखता है कि राजनीतिक लामबंदी के माध्यम से राजनेता अपने–अपने समुदायों के नाम पर खुद अपने और अपने परिवारों के हितों की रक्षा करने की जुगत में लगे रह कर गैरसमतावादी समाज को पुष्ट करने में लगे रहे हैं। जातियों के समूहों को भी इसी में अपना हित लगने लगता है, भले ही मलाई उन जातियों के नेता ले उड़ें। नागरिक समाज के संगठन भी इसी बहती गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इस खेल का सैद्धांतिक ढांचा ऐसा है कि जिनके पास अधिक शक्ति है वे लाभ का अनुपातहीन हिस्सा हासिल कर लेते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि आज भी भारतीय समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं बनी हुई हैं। जिनके पास सत्ता और धन की ताकत है सत्ता की संरचनाएं उनके अनुकूल होती चली जाती हैं। इसीलिए सभी लोग सत्ता के गलियारे में अपनी जगह बनाने की जुगत में लगे रहते हैं। स्पष्ट रूप से, वर्तमान संस्थानों की कार्यप्रणाली आर्थिक शक्ति के असमान वितरण और राजनीतिक शक्ति तक आम जन की असमान पहुंच से संचालित होती है। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक हैसियत में भी असमानता अपनी जड़ें जमा लेती है। इसने एक दुष्चक्र पैदा कर दिया है। असमान शक्ति संरचना संस्थानों की प्रकृति और कार्यप्रणाली और उनकी नीतियों को प्रभावित करती है। यह स्थितियां देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में गरीब की लोकतांत्रिक भागीदारी को बाधित करती हैं।

> **भारत में सिर्फ दस प्रतिशत लोगों के पास देश की आधे से भी ज्यादा 57 प्रतिशत संपत्ति है जबकि देश की आधी आबादी सिर्फ 13 प्रतिशत संपत्ति पर गुजारा करने को मजबूर है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राजनैतिक दलों की प्राथमिकता केवल सत्ता पाना रह गया है। सदियों से चले आ रहे सामंती व्यवहार वाले समाज को बदल कर उसे लोकतान्त्रिक मूल्यों से पोषित करने का काम राजनेताओं और राजनीति ने बहुत पहले ही छोड़ दिया।**

लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, जिसमें कोई भी बालिग नागरिक निर्वाचन में खड़ा हो सकता है या खड़े हुए व्यक्तियों में से किसी एक को अपनी स्वेच्छा से मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। इसे लोकतंत्र में नागरिक की शक्ति का प्रयोग कहते हैं। नागरिक जब मतदान करता है तो वह अपना शासक नहीं चुन रहा होता है, अपना प्रतिनिधि चुन रहा होता है जिससे वह अपेक्षा होती है कि वह संसद या विधान सभाओं में जाकर नागरिक जो चाहते हैं वह बात करे। आज़ादी के बाद गणतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं हो पाया है। निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचित होकर शासक बन बैठता है और अपेक्षा करता है कि नागरिक उसके हिसाब से व्यवहार करे। यह लोकतंत्र के शीर्षासन की स्थिति है। इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहता कि उसका निर्वाचित प्रतिनिधि सदनों की कार्यवाही बाधित करे, वहां शोर मचाए या धरना दे। देश का नागरिक चाहता है कि उसका प्रतिनिधि विधि निर्माता के रूप में प्रत्येक बहस में गंभीर भागीदारी करे और सदनों में नागरिकों के जीवन से जुड़े मुद्दों के हल के लिए हां पक्ष और ना पक्ष के बीच मोटी सहमति हो, न कि झगड़ा हो। कोई उलझा हुआ मुद्दा हो तो निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों के पास आये और जानें कि आम अवाम क्या चाहता है। मगर यहां सवाल स्वाभाविक ही उठ खड़ा होता है कि निर्वाचन की संविधान सम्मत व्यवस्था के बाहर प्रबुद्ध नागरिक समाज के केंद्र कहां हैं? भारतीय समाज धर्मों, जातियों और पंथों में बिखरा हुआ है। निर्वाचन प्रणाली में इस बिखराव का चतुर राजनेता लाभ उठाते हैं और एक सुंदर लोकतंत्र सपना ही बना रह जाता है। इस बिखराव से निर्वाचित राजनेताओं पर नागरिकों का अंकुश नहीं रह पाता। चुनाव के लिए प्रत्याशी चुनने में भी नागरिकों की कोई भूमिका नहीं होती। जनतान्त्रिक समाज की आदर्श व्यवस्था तो यह होती है कि नागरिक ही अपने प्रत्याशी चुनें और फिर बहुमत से उनमें से किसी एक को सदनों में भेजे। मगर प्रत्याशियों के चयन का काम राजनैतिक दल करते हैं और नागरिकों को उन्हीं के चयन पर मतदान करना होता है। जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रांति की ललकार के बाद सभ्य समाजों ने ऐसे थोड़े बहुत प्रयास जरूर किये कि नागरिक अपने प्रत्याशी खुद चुनें। मगर दलविहीन राजनीति का यह प्रयोग सम्पूर्ण क्रांति की भांति असफ़ल रहा। इसके लिए जिस प्रकार की ज़मीन तैयार करने की जरूरत होती है वैसा करने वाला कोई सशक्त संगठन नहीं बन पाया। जेपी आंदोलन से निकल कर राजनीति में गये युवाओं में से भी अनेक बाद में जाकर बुरे राजनेता साबित हुए। पिछले दो दशकों में ऐसे आंदोलन भी उभरे जिनसे लोगों को लगा कि नई सुबह आने ही वाली है, मगर उन्हें निराश ही हाथ लगी। लोकतंत्र की सफलता के लिए आम अवाम का भी संजीदा और समझदार होना अपेक्षित होता है। हमारे देश में अवाम की वैसी शिक्षा कभी हो नहीं पाई। जनता को लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए जागरूक करने में राजनीतिक दलों व उनके कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका होती है। ऐसा नेतृत्व का उभरना तभी संभव है जब आमजन लोकतन्त्र और राजनीति के प्रति उदासीनता त्याग कर आभासी सोशल मीडिया पर आलोचनाओं और बहसों से आगे बढ़कर ज़मीनी स्तर पर काम करे और राज्य के संचालकों से दृढ़ता से सवाल करे और जवाब मांगे।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

विश्वविद्यालय वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का निर्माण करें : राज्यपाल

- कोटा विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोटा विश्वविद्यालय में 60 छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं 49 विद्यावाचस्पति उपाधियां प्रदान की।

कोटा, (निसं)। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि विश्वविद्यालय वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का निर्माण करें। उन्होंने विश्वविद्यालयों को कौशल विकास से संबंधित शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए 'विकसित भारत 2047' की संकल्पना को साकार करने का आव्हान किया।

राज्यपाल मंगलवार को कोटा विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्या वाचस्पति अभ्यर्थियों को गोल्ड मेडल एवं उपाधियां प्रदान करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में कन्या छात्रावास, धनवन्तरी भवन एवं बॉस्केबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि नव–जीवन का प्रारंभ है। यह वह अवसर है जब विद्यार्थी प्राप्त शिक्षा का राष्ट्र और समाज के उत्थान में उपयोग करने के लिए तैयार होता है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने साक्षी जैन को कुलाधिपति पदक, पूजा साहू को कुलपति पदक जबकि 60 छात्र–छात्राओं स्वर्ण पदक एवं 49 विद्यावाचस्पति उपाधियां प्रदान की। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से कुल 88 हजार 692 उपाधियां प्रदान की गई हैं। इनमें 43 हजार 677 छात्र (49 प्रतिशत) एवं 45 हजार 15 छात्राएं (51 प्रतिशत) शामिल हैं। राज्यपाल ने 51 फीसदी छात्राओं के उपाधि हासिल करने एवं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने पर खुशी जताते हुए कहा कि बेटियों को अवसर प्रदान किए जाएं तो वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। छात्राएं अपनी प्रतिभा का समुचित सदुपयोग कर निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने आव्हान किया कि छात्र–छात्राएं सामूहिक सहयोग से विकसित भारत का संकल्प पूरा करें। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा देश अपने अमृत काल में है।

जी–20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और इस कार्यकाल ने भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभारा है। भारत इस समय विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत के भविष्य को गढ़ने के सबके प्रयास एक नए भारत की नींव का निर्माण करने वाले है। मुझे विश्वास है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में समुचित विश्व का नेतृत्व करेगा।

राज्यपाल ने कहा कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल विकास आधारित शिक्षा पर केन्द्रित है। यह रोजगारोन्मुखी होने के साथ चरित्र–निर्माण, ज्ञान–विज्ञान व आध्यात्मिक विकास के साथ देश और समाज की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ी है। कोटा विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्रेडिट आधारित सेमेस्टर प्रणाली लागू करने तथा इस ग्रेडिंग प्रणाली में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के साथ–साथ नैतिक मूल्य आधारित कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की उन्होंने सराहना की।

उन्होंने कहा कि कोटा विश्वविद्यालय ने स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए सतत् मूल्यांकन को जोड़कर प्रदेश में एक अनूठी पहल की है। समारोह की शुरूआत में राज्यपाल ने संविधान की उद्देशिका एवं मूल कर्तव्यों का वाचन किया। दीक्षान्त भाषण में वनस्थली विद्यापीठ की कुलपति प्रो. ईना आदित्य शास्त्री ने कहा कि शिक्षा का ध्येय मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य का चारित्रिक निर्माण तथा ज्ञान के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का विकास है। विश्वविद्यालय की कुलपति, प्रो नीलिमा सिंह ने विश्वविद्यालय प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरूआत में कुलपति प्रो.नीलिमा सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया। अंत में कुलसचिव प्रो.रीना दाधिच ने धन्यवाद ज्ञापित किया। दीक्षान्त समारोह में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रो. कैलाश सोडानी, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रो.एसके सिंह, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.अभय कुमार व्यास सहित कला, समाज विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, विधि संकाय व जीव विज्ञान के अधिष्ठाता उपस्थित थे।

ग्वार की अवैध खेती से वन्यजीवों के संरक्षण में आई बाधा

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर जिले में वन विभाग की जमीन पर अतीकर्मियों द्वारा ग्वार की खेती कर के अरबों रूपये कमाने के दौरान वन्यजीवों के जीवन पर भारी संकट आया उस दौरान ग्वार के भाव 6 गुना बढ कर 3सौ रुपए प्रति किलोग्राम हो जाने से स्वार्थी लोगों ने वन विभाग के कर्मचारियों से मिल कर वन्यजीवों की जमीन को भी नही बक्सा सरकारी जमीन पर वन्यजीवों के शत्रु बन कर कानून को अपने हाथ में लेकर गोडावण व अन्य जीवों के संरक्षण को धता बताते हुए कृत्य करने वालों को कोई आंच नहीं आई।

हालांकि वन्य एरिया में लगी हाइटेंशन लाइनें भी गोडावण की मौत के लिए जिम्मेदार है। जिसे लेकर वन्यजीव प्रेमियों द्वारा कई बार विरोध भी जताया जा चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन हाइटेंशन लाइनों को अंडरठाग्राउंड करने को लेकर कई बार पाबंद भी किया है। लेकिन इसके बावजूद अब तक हाइटेंशन लाइनों को अंडरग्राउंड नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गोडावण व अन्य जीवों के सरंक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करके जैसलमेर भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति का गठन कर उन्हें वन्यजीवों के संरक्षण के उपायों के साथ ही ओवरहेड व अंडरग्राउंड केबल व दायरे का निर्धारण करने का काम सौंपा। 30 जून को समिति के पदाधिकारी जैसलमेर पहुंचे । उन्होंने सोमवार को फील्ड विजिट कर अपनी रिपोर्ट तैयार की।

गौरतलब है कि अब तक हाइटेंशन लाइन से टकराने पर करीब 9 गोडावणों की मौत हो चुकी है। 2021 में पर्यावरणविद और वन्यजीव विशेषज्ञ एमके रंजीत ने एक रिट याचिका पेश कर समिति के गठन की बात की थी। उन्होंने ऊर्जा संयंत्रों के पास हाइटेंशन वाले तारों से टकराने पर वन्यजीवों व गोडावण की मौत पर प्रकाश डाला था। जिस पर मामले में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में सात सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया था।जैसलमेर के डीएनपी एरिया के आस पास सोलर प्लांट आ गए हैं। जिससे नए जीएसएस का निर्माण किया जा रहा है। इन्हीं जीएसएस तक बिजली आपूर्ति करने के लिए हाइटेंशन लाइनें बिछाई गई है। डीएनपी क्षेत्र में कुछ जगह अंडरग्राउंड केबल करना असंभव है।

ऐसे में उन जगहों को चिन्हित कर वहां बर्ड डायवर्टर लगाएं जाएं। हालांकि कुछ जगह बर्ड डायवर्टर लगाए जा चुके हैं। लेकिन कुछ जगह अंडरग्राउंड केबल भी बिछाई जा सकती है। वन्यजीवों के लिहाज से हाइटेंशन लाइन उनकी उड़ान में बाधा बन रही है। वहीं जैसलमेर के लिहाज से सोलर प्लांट भी काफी महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के निदेशक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के सदस्य डॉ हरिशंकर सिंह, पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ निरंजनकुमार वासु, पूर्व मुख्य वन्यजीव वार्ड और महाराष्ट्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी मजूमदार, कार्बेट फाउंडेशन उपनिदेशक डॉ देवेश गढ़वी, ऊर्जा विभाग के नवीन और नवीनीकरण संयुक्त सचिव ललित बोहरा तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव को जैसलमेर भेजा है। इनके साथ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य अशोककुमार राजपुर व सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी पीसी गर्ग को विशेष आमंत्रित सदस्य बना कर भेजा है। गोडावण संरक्षण के लिए गठित विशेषज्ञ टीम ने मुख्य रूप से बिजली लाइनों पर स्थापित बर्ड डायवर्टर की गुणवत्ता को चेक किया साथ ही बर्ड डायवर्टर के लिए उच्च मानक तय किया । इसके अलावा यह भी देखा कि फील्ड में लगे सभी बर्ड डायवर्टर अपनी मानकों पर खरे उतर रहे है या नहीं। समिति ने बर्ड डायवर्टर के साथ ही अंडरग्राउंड केबल का भी निरीक्षण किया ।

जिले के वरिष्ठ नागरिक कमल ने बताया कि ज्यादातर सर्वे करने वाली टीमों में आने वाले यहाँ मौज मस्ती करके चले जाते है इस बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई टीम आई है तो वन्यजीवो के हित में कुछ समाधान होने की उम्मीद की जा सकती है।

डीएफओ डीएनपी आशीष व्यास ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित हुई कमेटी के सदस्यों ने जैसलमेर पहुंच कर दो दिन तक फील्ड विजिट किया। हाइटेंशन लाइनों को अंडरग्राउंड करवाने की बात कहते हुए कमेटी के सदस्यों ने गोडावण संरक्षण की रिपोर्ट बनाई है।

छबड़ा से कडैयानोहर को जोड़ने वाली संपर्क सड़क का हाल बेहाल, आवागमन बाधित

छबड़ा (निसं)। आज भी ग्रामीण अंचलों में सड़क की समस्या महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है।

छबड़ा से कडैयानोहर को जोड़ने वाली संपर्क सड़क का हाल खस्ता होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर वाहन चलाने को मजबूर हैं।

छबड़ा से कडैयानोहर को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण खांकरा, कडैयानोहर, कुण्डी, पटना, लोधपुरिया, अमीनपुरा, खेरखेड़ानाथूराम, युसुफपुरा आदि गांव के ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही हैं और यह समस्या वर्षा के दिनों ओर अधिक बढ़ जाती है। इस क्षतिग्रस्त सड़क पर से वाहन लेकर चलना तो दूर की बात है पैदल चलना भी मुसीबत से कम नहीं है। कहीं–कहीं तो इस सड़क पर बड़े–बड़े गड्ढे हो चुके हैं। राहगीर इस रास्ते से जान जोखिम में डालकर गुजरने को मजबूर हैं। सड़क का खस्ताहाल रोजाना हादसों को न्यौता दे रहा है। सड़क जर्जर होने के कारण षिक्षक, ग्रामीण कमर दर्द से पीड़ित होने लगे हैं।

स्कूल आने–जाने वाले बच्चों को परेशानी:– ग्रामीणों के अनुसार बारिश के सीजन में स्कूल आते–जाते समय इस क्षतिग्रस्त सड़क से गुजरने वाले विद्यार्थी कीचड़ में फिसल कर अनेकों बार गिर चुके हैं। उनकी यूनीफार्म तक खराब हो जाती हैं। मार्ग में पानी जमा होने व दलदल की वजह से विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो जाती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षा का मौसम उनके लिए वनवास जैसा हैं। ना साइकिल चल पाती हैं ना दोपहिया वाहन।

छबड़ा से कडैयानोहर को जोड़ने वाली संपर्क सड़क का हाल खस्ता होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर वाहन चलाने को मजबूर है।

मरीज चिकित्सालय तक नहीं पहुंच पाते:– ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई बीमार हो जाएं तो गांव तक एम्बुलेंस नहीं आ पाती। मुख्यालय तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पडता हैं। बरसात में जहरीले जीव जंतुओं का डर हमेशा बना रहता हैं। इसके अलावा आसपास के गांवों की आबादी भी इस खराब सड़क की वजह से परेशानी झेल रही है। यह सड़क गांव के लोगों के लिए मुख्य सड़क है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण जरा सी बरसात में यह मार्ग न केवल कीचड़ में तब्दील हो जाता, बल्कि सामान्य मौसम में भी ऊबड खाबड़ के हालात बने रहते हैं। बारिश की वजह से कई स्थानों पर जलभराव जैसी नौबत बन जाती है।

राशिफल बुधवार 3 जुलाई, 2024

पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2081, रोहिणी नक्षत्र रात्रि 4:07 तक, शूल योग प्रातः 9:01 तक, तैतिल करण प्रातः 7:11 तक, चन्द्रमा वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–मिथुन, चन्द्रमा–वृष, मंगल–मेष, बुध–कर्क, गुरू–वृष, शुक्र–मिथुन, शनि–कुम्भ, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से सम्पूर्ण दिन–रात है। आज प्रदोष व्रत, रोहिणी व्रत (जैन) है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ–अमृत सूर्योदय से 9:06 तक, शुभ 10:48 से 12:30 तक, चर 3:56 से 5:18 तक, लाभ 5:18 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:41, सूर्यास्त 7:20

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य के संबंध में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कर्क
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

तुला
व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेंगी। व्यावसायिक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

धनु
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा है।

मकर
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर–परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ
घर–परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। घर–परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।